इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 11 जून 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------5
सूक्ष्मवित्त ----------5
विदेशी मुद्रा ----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड़ ----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्रामीण एजेन्ट अब सभी ग्राहकों की जरूरतें पूरी करेंगे

वित्त मंत्रालय के निदेशों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब अपने कारबार संपर्कियों (BCs) को सभी बैंकों के ग्राहकों की सेवा करने के निर्देश दे रहे हैं। कारबार संपर्की जिस किसी भी बैंक से क्यों न सम्बद्ध हो, हस्त-चालित उपकरणों से सुसज्जित उक्त एजेन्ट, जो चल (मोबाइल) एटीएमों के रूप में काम करता है, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता रखने वाले किसी भी ग्रामीण से नकदी स्वीकार करेगा और उसे नकदी प्रदान करेगा। ग्रामीण भारत में बैंकिंग लेनदेन को अधिक आसान बनाने के उद्देश्य वाली इस मुहिम से उस वित्तीय समावेशन में गहनता आ सकती है, जो सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

सार्क के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) के सदस्य देशों की अल्पावधिक आकस्मिक सहायता के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर की मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था की घोषणा की है। इस व्यवस्था के माध्यम से सदस्य राष्ट्र अपनी घरेलू मुद्रा अथवा सरकारी प्रतिभूतियों की डालर, यूरो अथवा रुपये के लिए अदला-बदली कर सकते हैं।

बैंकों को कृषकों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करने के लिए कहा गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों से संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए उन्हें स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड प्रदान करने के लिए कहा है। इन कार्डों को एटीएमों, हाथ में रखी जाने वाली स्वाइप मशीनों, बिक्री केन्द्र (PoS) टर्मिनलों तथा मोबाइल बैंकिंग में प्रयोग के लिए अनुकूल होना चाहिए और उन्हें किसानों की पहचान, आस्तियों, जोतों एवं ऋण प्रोफाइल

से सम्बन्धित पर्याप्त सूचना को भण्डारित करने में भी समर्थ होना चाहिए। यह मुहिम किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। जहां नामे और जमा लेनदेनों के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं होगी, वहीं प्रत्येक कार्ड की एक ऋण सीमा होगी। इसके अलावा, कृषक कारबार संपर्कियों, निविष्टि व्यापारियों, व्यापारियों एवं मंडियों के पास मौजूद बिक्री केन्द्र मशीनों के माध्यम से भी लेनदेन कर सकते हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

अन्त: बैंक खता अंतरण के लिए नये सिरे से अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि आवश्यक नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय किया है कि बैंक की एक शाखा द्वारा एक बार पूरी की गई अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया बैंक के भीतर खाते के अंतरण के लिए वैध होगी, क्योंकि अधिकांश बैंक शाखाएं अब कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS) के अधीन आ गई हैं तथा अपने ग्राहक को जानिए से सम्बन्धित रिकार्ड तक बैंक की किसी भी शाखा की पहुंच हो सकती है। इसप्रकार ग्राहक को अपने खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थांतरित करने की अनुमति किसी प्रतिबंध के बिना तथा जैसा कि कुछेक बैंकों द्वारा जिस पर बल दिया जाता है, दूसरी शाखा में एक नया खाता खोलने की आवश्यकता के बिना दी जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख निवेश कम्पनियों के विदेशी परिव्यय के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख निवेश कम्पनियों (CICs) को विदेशी वित्तीय आस्तियों में उनकी स्वाधिकृत निधियों के 200% तक तथा विदेशी गैर-वित्तीय आस्तियों में उनकी निधियों के 400% तक निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। उन प्रमुख निवेश कम्पनियों को, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, उनके विदेशों में वित्तीय आस्तियों में निवेश करने की इच्छुक होने पर बैंक के पास पंजीकरण कराना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख निवेश कम्पनियों (CICs) से विदेशों में स्थित स्थानों पर शाखाएं न खोलने के लिए कहा है तथा यह कहा है कि ऐसी फर्मों की तथाकथित सहायक विदेशी कम्पनियों को शेल (shell) कम्पनियां नहीं होना चाहिए। ऐसी सहायक कम्पनियों को भारतीय परिचालनों के लिए आस्तियां सृजित करने हेतु विदेशी संसाधन जुटाने से रोक दिया गया है।

व्यसायियों के खाते खोलने से पहले आय कर विवरणी सत्यापित कर लें : शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

धोखाधड़ियां रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया के एक अंग के रूप में व्यवसायियों के खाते खोलने से पहले आय कर

विवरणियां सत्यापित कर लें। शहरी सहकारी बैंकों को एकल स्वत्वाधिकारी के नाम पर उन सम्पूर्ण आय कर विवरणियों का सत्यापन कर लेना चाहिए, जिनमें आय कर प्राधिकारियों द्वारा फर्म की आय अधिप्रमाणित की जाती है तथा उन्हें स्वत्वाधिकारी फर्मों के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिलों जैसे उपयोगिता बिलों की भी जांच कर लेनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यातकों, बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों और बैंकों को उनके द्वारा डालर निधियों को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किए जाने पर एक पखवाड़े के भीतर दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने की धमकी दी है। यह मुहिम उस दिन आरंभ हुई जिस दिन रुपये में तीव्र उतार-चढ़ाव परिलक्षित हुआ - वह दिन के न्यून स्तर से 73 पैसे बढ़ कर दिन की समाप्ति पर 55.66 प्रति डालर पर बंद हुआ। मुद्रा में पिछले दिन की समाप्ति के स्तर की तुलना में 0.6% की बढ़ोत्तरी हुई। हालांकि, प्रारंभिक क्रय-विक्रय के दौरान वह अमरीकी डालर के समक्ष 56.39 के नये अंत: दिवसीय न्यून स्तर पर पहुंच गया।

रुपये के कमजोर पड़ने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानदंड शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की 1 से लेकर 3 वर्ष तक की परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों की ब्याज दर की उच्चतम सीमा को लिबोर अथवा अदला-बदली दर की इस समय के 125 आधार अंक से शिथिल कर के 200 आधार अंक कर दिया है। 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों पर दर की उच्चतर सीमा शिथिल कर के लिबोर से 300 आधार अंक अधिक कर दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की अनुमति भी दे दी है। सामान्य वंचन-विरोधी नियमों (GAAR) तथा तेल की कीमतों में सुधार जैसे नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण भारतीय मुद्रा की नियति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

स्वर्ण ऋण देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रति ऋण जोखिम में कमी लाएं : बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुख्यतया स्वर्ण ऋण व्यवसाय में लगी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रति बैंकों के ऋण जोखिम से सम्बन्धित मानदंडों को और भी कठोर बना दिया है। बैंकों से उसकी कुल वित्तीय आस्तियों के 50% या उससे अधिक की सीमा तक स्वर्ण ऋण देने वाली एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के प्रति उनके विनियामक ऋण जोखिम (exposure) की उच्चतम सीमा को उनकी पूंजीगत निधियों के मौजूदा 10% से घटा कर 7.5 % कर देने के लिए कहा गया है। अब बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे सभी स्वर्ण ऋण कम्पनियों के प्रति अपने समग्र ऋण जोखिम के सम्बन्ध में एक आंतरिक उप-सीमा निर्धारित करें । ये उप-सीमाएं कुल मिला कर सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए उनके समग्र ऋण जोखिम हेतु बैंकों द्वारा निर्धारित आंतरिक सीमा के भीतर होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से जोखिम पूंजी की आरक्षित निधि जुटाने हेतु कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अधिक जोखिम पूंजी अलग से रखने तथा बासेल- III मानदंडों को अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कहा है। भारतीय बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी जोखिमपूर्ण आस्तियों (ऋणों) के लिए न्यूनतम 5.5% की (टियर-I) साझी इक्विटी पूंजी अलग रखें। बैंकों को उनकी जोखिमपूर्ण आस्तियों (ऋणों) के लिए न्यूनतम 1.5% की अतिरिक्त इक्विटी की भी व्यवस्था करनी है। चलनिधि के अभाव से निपटने के लिए बैंकों को साझी इक्विटी के रूप में 2.5% का पूंजी संरक्षण भण्डार तथा उसके साथ ही 2% की टियर-I पूंजी भी अलग रखनी है। अंत में बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे प्रति चक्रीय सुरक्षित भण्डार के रूप में 2.5%की साझी इक्विटी भी अलग से सृजित करें। इसलिए बैंकों को जो पूंजी अलग रखनी है वह 14% है।

उच्च मूल्य वाले चेकों के लिए अतिरिक्त लागत के आधार पर प्रभार नियत करें

ऐसे बैंकों को, जिन्होंने 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले लिखतों के लिए बाहरी केन्द्रों अथवा गतिशील समाशोधन हेतु अपने सेवा प्रभार उन लिखतों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में निर्धारित कर रखे हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसकी समीक्षा करने तथा उनका निर्धारण अतिरिक्त लागत के आधार पर करने की सलाह दी गई है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे चेक समाशोधन के लिए संशोधित सेवा प्रभार ढांचे के बारे में अपने ग्राहकों को सूचित करें। इस बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेकों की तीव्र गति से वसूली एवं बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक समाशोधन गृह रहित स्थानों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। बैंकों से यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है कि अन्य बैंकों पर आहरित लिखत प्रत्येक कार्य दिवस को पारस्परिक रूप से निर्धारित स्थान एवं समय पर सुपुर्द अथवा दिए-लिए जाएं। ऐसा करते समय बैंकों को आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक पर हुई कार्यवाही की जानकारी उसी दिन हो जाए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैकों की वृद्धिशील इक्विटी आवश्यकता नियंत्रणीय है

साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) को लगता है कि बासेल-III पूंजी पर्याप्तता मानदंडों से उद्भूत हुई बैंकों की वृद्धिशील इक्विटी आवश्यकता 'नियंत्रणीय' है। भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) ने अनुमान लगाया है कि बैंकों को आगामी छ: वर्षों में 3.9 लाख करोड़ रुपये और 5 लाख करोड़ रुपये के बीच आवश्यकता होगी, जिसमें से 'साझी इक्विटी' वाला अंश 1.3 लाख करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये तक होगा। अतिरिक्त टियर-I के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये तथा टियर-II के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की एक और आवश्यकता होगी। भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) का अनुमान

है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्त मंत्रालय की शेयरधारिता को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आवश्यकता में से सरकार का हिस्सा 30,000-80,000 करोड़ रुपये होगा।

शहरी सहकारी बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत ऋण प्रदान कर सकते हैं

वर्धित उधार को सुगम बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार योजना के तहत व्यक्तियों को 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण मंजूर करने के लिए कुल आस्तियों के 5% की अतिरिक्त सीमा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की जिंस बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों से सम्बन्धित नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा जिंस बाज़ारों (comexes) में निवेश के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जिंस बाज़ारों (comexes) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के लिए इस अननुमोदन की आवश्यकता होगी । जिंस बाज़ारों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की अधिकतम सीमा 26% है, जबकि समग्र विदेशी निवेश की सीमा 49% है। पोर्टफोलियो निवेश योजना के अधीन विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा समग्र सीमा के भीतर 23% निर्धारित है।

एटीएम खोलने, लागत कम करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक साथ आएंगे

इस वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 65,000 से अधिक एटीम खोलने के लिए एक साथ आगे आएंगे। इससे सभी सदस्य बैंकों की परिचालन लागत में (लेनदेन लागत को कम करते हुए) कम से कम 30% की कमी आएगी, क्योंकि किसी विशिष्ट स्थान पर एटीएमों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि होगी, जिससे उन्हें विक्रेताओं के साथ लेनदेन प्रभार नियत करने में और अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त होगी। पिछले वर्ष में, विक्रेताओं ने बैंकों से प्रति एटीएम लेनदेन 13-16 की श्रेणी में प्रभार वसूल किया था। एकीकृत दृष्टिकोण में यह लागत प्रति लेनदेन 30-38% से घट कर 8-11 हो जाएगी। इसके अलावा, प्रति एटीएम लेनदेनों के प्रति दिन 250 से अधिक होने पर प्रभारों में 40% की एक और कमी आएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पदोन्नति नीति शिथिल की गई

एकबारगी उपाय के रूप में वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पदोन्नति नीति को शिथिल बना दिया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि बैंक अगामी कुछेक वर्षों में भारी संख्या में अधिवर्षिता पर विचार कर रहे हैं। इन बैंकों द्वारा विचारणीय संस्तर में अधिकारियों की अनुपलब्धता; वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के अंकों तथा पदोन्नतियों के लिए पात्रता की निर्दिष्ट तिथियों के सम्बन्ध में महसूस की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने

पदोन्नति मानदंडों को शिथिल कर दिया है। अब पदोन्नति के लिए विचारणीय संस्तर (Zone of consideration) सामान्यतया प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगा। निदेशक मण्डल सेवा-काल में न्यूनतम पात्रता के मानदंडों को मार्च में जारी दिशानिर्देशों में पहले से की गई एक वर्ष की व्यवस्था के अलावा और भी शिथिल कर सकता है।

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कारबार संपर्की केन्द्र खोल सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को ग्रामीण केन्द्रों में करबार संपर्कियों के लिए केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये कारबार संपर्की केन्द्र अल्प लागत वाले सामान्य ईंट-गारे वाले ढांचे हो सकते हैं। वे बैंकों की अति लघु शाखाओं से परिचालन कर सकते हैं, क्योंकि शाखा के साथ उनकी संलग्नता उस क्षेत्र में वैधता एवं विश्वसनीयता बढ़ाएगी तथा उनकी सेवाओं के बारे में लोगों का विश्वास बढ़ाएगी।

चलनिधि को सुगम बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार के परिचालनों की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि के दबाव से चिंता मुक्त करने और सरकारी बॉण्डों की नये सिरे से आपूर्ति के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये तक की पूंजी लगा सकती है। केन्द्रीय बैंक बहुविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के चार लॉट खरीदेगा। बाज़ार के सहभागियों का मत यह है कि भातीय रिज़र्व बैंक ने यह उपाय विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में उसके हाल के हस्तक्षेप से निर्मित चलनिधि सम्बन्धी दबावों को निष्प्रभावी करने हेतु किया होगा। इस कार्रवाई से सरकारी बॉण्डों की भारी मात्रा में साप्ताहिक नीलामी के लिए अवसर सृजित करने में भी सहायता प्राप्त होगी। सरकार ने 2011-12 में जुटाए गए 5.1 लाख करोड़ रुपये की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 5.69 लाख करोड़ रुपये का सकल बाज़ार उधार जुटाने का लक्ष्य नियत किया है। इससे ऋण बाज़ारों का साप्ताहिक भार 2011-12 में 12,000-15,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर इस वर्ष 16,000-18,000 करोड़ रुपये हो गया है।

ऋण 17.27% बढ़े

वाणिज्यिक बैंकों ने 4 मई को समाप्त पखवाड़े में 26391 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण संवितरित किए। ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि 17.27% रही। वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम 46,44,071 करोड़ रुपये थे। इस समय ऋण का उठाव मंद है, क्योंकि यह वर्ष की शुरूआत है।

वित्तीय समावेशन को शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करें

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपने वित्तीय समावेशन अभियान को शहरी भारत तक फैलाने के लिए कहा है, ताकि प्रवासी मजदूर भी इसका लाभ उठाने में समर्थ हों। मंत्रालय ने बैंकों से

प्रवासियों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की ओर आकर्षित करने हेतु एक विशेष अभियान छेड़ने के लिए कहा है। इसके अलावा, उसने ऋणदाताओं का शहरी क्षेत्रों में मजदूरों, सड़क पर माल बेचने वालों, फेरीवालों का बचत बैंक खाता खोलने का आह्वान किया है। प्रारंभ में, बैंकों को उन मज़दूरों के खाते खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जो किसी बैंक की शाखा से 500 मीटर के भीतर वाले स्थान पर रहते हों।

शहरी सहकारी बैंक विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों पर अधिक ब्याज दे सकते हैं

देश में अधिक डालर लाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों की शहरी सहकारी बैंकों में रखी गई विदेशी मुद्रा जमाराशियों (विमुअनि-बैंक) पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। शहरी सहकारी बैंकों में 1-3 वर्ष की विदेशी मुद्रा जमाराशियों की दरों पर उच्चतम सीमा लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) की पूर्ववर्ती 125 आधार अंक अधिक से बढ़ा कर 200 आधार अंक कर दी गई है। 3 से 5 वर्ष की जमाराशियों पर शहरी सहकारी बैंक पूर्ववर्ती केवल 125 आधार अंक के बजाय लिबोर से 300 आधार अंक अधिक की दरें प्रदान कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में बढ़ोत्तरी, किन्तु चेक के लेनदेन अधिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश में उच्च मूल्य वाले लेनदेनों का भुगतान करने के लिए चेक अब भी अधिमानी विधि हैं। 2011-12 में चेक से किए गए भुगतानों की रकम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करते हुए भुगतान की गई 22 लाख करोड़ रुपये के समक्ष 98.9 लाख करोड़ रही। वर्ष के दौरान 115.9 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्टॉनिक समाशोधन सेवा (ECS) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) हुए। यह चेकों के माध्यम से किए गए 134.1 करोड़ से थोड़ा कम था।

भारतीय रिज़र्व बैंक की दर वृद्धि

नवम्बर, 2011 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 वर्ष से अधिक वाले अनिवासी विदेशी खातों पर न्यूनतम ब्याज दरों को लिबोर / अदला-बदली से 275 आधार अंक बढ़ा दिया था। दिसम्बर 2011 में अनिवासी खातों पर जमा दरें विनियंत्रित कर दी गईं। इसके पूर्व इस माह में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अनिवासी की ब्याज दरों से सम्बन्धित सीमा में 1-3 वर्ष की जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली दर से 200 आधार अंक तथा 3-5 वर्ष की अवधि वाली जमाराशियों के लिए 300 आधार अंक की बढ़ोत्तरी कर दी थी।

बैंकों से निदेशक मण्डल की बैठकें मुख्यालय में आयोजित करने हेतु कहा गया

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को एक परिपत्र भेजा है, जिसमें उन्हें अपने निदेशक मण्डलों की बैठकें पर्यटन स्थलों पर नहीं, अपितु अपने मुख्यालय में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के पत्र में प्रधान कार्यालयों और अंचलीय अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों के बीच बैठकों के लिए वीडियो वार्तालाप का उपयोग किए जाने को भी प्रोत्साहित किया गया है।

बैंकों से बीमा सुरक्षा बढ़ाने से पहले जोखिम प्रबन्धन अपनाने हेतु कहा गया

सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक और निक्षेप, बीमा, प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) से बैंक जमाराशियों के लिए बीमा सुरक्षा को दोगुना बढ़ा कर 2 लाख रुपये करने से पहले जोखिम प्रबन्धन प्रणाली अपनाने के लिए कहा है। निक्षेप, बीमा, प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) के वर्तमान मानदंडों के अनुसार किसी बैंक के दिवालिया होने पर जमाकर्ता को अधिकतम 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। हालांकि, अब बैंकिंग प्रणाली के हित में निक्षेप, बीमा, प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) को निक्षेप बीमा सुरक्षा को बढ़ाना पड़ सकता है।

रुपये की अस्थिरता पर सरकार की नज़र

वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री कौशिक बसु ने कहा है कि अस्थिर रुपये के प्रति सरकार अत्यधिक चिंतित है और वह उस पर गहन रूप से निगरानी रख रही है। यूरो क्षेत्र की किसी भी प्रकार की संभाव्य विफलता का भारत पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव होगा तथा 2014 में एक और यूरोपीय संकट की संभावना है। सॉवरेन ऋण संकट को रोकने के लिए यूरोपीय बैंकों को दिए गए 1.3 ट्रिलियन डालर के भारी मात्रा में अल्प लागत वाले ऋणों की 2014 में चुकौती की जानी होगी। श्री बसु ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2011-12 में अनुमानित 6.9% के समक्ष 2012-13 में लगभग 7.6% की वृद्धि होगी। रुपये में अचानक उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है।

विनियामकों के कथन

आपूर्ति प्रणाली मांग के अनुरूप कार्य नही कर रही

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण के अनुसार "खाद्यान्न मूल्य की मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आपूर्ति पक्ष से सम्बन्धित मुद्दों का निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति इसलिए बनी रही, क्योंकि आपूर्ति प्रणाली की अनुक्रिया मांग के अनुरूप नहीं रही। हमारे लिए दबाव के इस स्रोत का निराकरण करना आवश्यक है। हमारे लिए कृषि उत्पादकता, भण्डारण सुविधाओं तथा वितरण नेटवर्क को बढ़ाना आवश्यक है। सरकार उपभोग और आर्थिक सहायता पर अधिक खर्च कर

रही है। हम जब तक सार्वजनिक खर्च को क्षमता निर्माण की दिशा में वापस नहीं ला सकते, तब तक सकल निवेश में वृद्धि नहीं होगी।"

वित्तीय प्रणाली "अब भी सुदृढ़ है"

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली अब भी सुदृढ़ है। "भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक मूल्यांकन से यह पता चलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैश्विक साख निर्धारण एजेन्सी स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स ने धीमी राजकोषीय प्रगति और बिगड़ते आर्थिक संकेतकों के कारण भारत की संभावना को स्थिर से घटा कर नकारात्मक कर दिया है। स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स की इस पदावनति के प्रभाव पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए डॉ. चक्रवर्ती ने कहा कि मुद्रा बाज़ारों में भारतीय रिज़र्व बैंक का हस्तक्षेप अस्थिरता के स्तर पर निर्भर करेगा। बाज़ारों ने स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स ने जो कहा था उसके प्रभाव की पहले ही उपेक्षा कर दी है।"

अनर्जक आस्तियों में वृद्धि बैंकिंग प्रणाली पर दबाव का निरूपण करती है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने कहा कि मार्च 2010 से अनर्जक आस्तियों में वृद्धि बैंकिंग प्रणाली में दबाव का निरूपण करती है। दबाव की स्थिति में विसर्पण (slippage) और वसूली प्रतिलोमी रूप से सम्बन्धित होते हैं तथा विसर्पण वसूलियों से काफी अधिक रहे हैं।

बैंकों को वित्तीय समावेशन में मुख्य भूमिका निभानी होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी; चक्रवर्ती के अनुसार वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए उपयुक्त सुपुर्दगी मॉडेल महत्वपूर्ण होते हैं। "वित्तीय समावेशन में मुख्य भूमिका बैंकों द्वारा निभाई जानी है। उनके लिए वित्तीय समावेशन के तहत खोले गए खातों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। सार्थक वित्तीय समावेशन का सूत्रपात्र करने के लिए आवश्यक उत्पादों की सम्पूर्ण संजाति केवल बैंक ही प्रदान कर सकते हैं। उनके लिए वित्तीय समावेशन में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों जैसी अन्य एजेन्सियों के साथ सहयोग करने में भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे केवल सहायक भूमिका ही निभा सकती हैं। वित्तीय समावेशन उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय साक्षरता के साथ वृहत्रयी का एक भाग था, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे।"

अर्थव्यवस्था में हल्का पुनरुत्थान हो सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि कतिपय वित्तीय एवं बाहरी दबावों के नीतिगत परिवेश को दृढ़तापूर्वक प्रभावित करने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में हल्का पुनरुत्थान परिलक्षित होने की संभावना है। "वर्ष 2012-13 की प्रत्याशा के अनुसार वृद्धि में हल्का पुनरुत्थान होने वाला है। अप्रैल वाली हमारी नीति में हमारे अनुमानों से यह पता चलता था कि सकल घरेलू उत्पाद

(GDP) की वृद्धि 7.5% पर रहेगी। हम निश्चित रूप से वर्ष के दौरान इस प्रक्रिया से कुछ बुनियादी परिणामों की आशा करते हैं। यदि हम मुद्रास्फीति को रोकने पर ध्यान केन्द्रित रखना चाहते हैं, तो मौद्रिक नीति को अन्य जोखिमों एवं दबावों के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील रखना होगा।" डॉ. गोकर्ण ने कहा कि घरेलू वृद्धि- मुद्रास्फीति संतुलन दोनों ही मोर्चों पर जोखिम बने रहने के बावजूद स्थिर हो रहा है।

वृद्धि के चर मंदी के संकेत देते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि मार्च महीने के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) कर आंकड़े वृद्धि में मंदी आने के लक्षणों को पुनर्बलित करते हैं। "यद्यपि वृद्धि से सम्बन्धित कार्यकलाप के एकल संकेतक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े इस बिन्दु पर किंचित अपर्याप्त है, अन्य चरों से भी यह संकेत प्राप्त होता है कि निश्चित रूप से मंदी आ रही है।"

रुपये को बचाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विकल्पों पर विचार करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक तेल का विपणन करने वाली कम्पनियों के विदेशी मुद्रा की अस्थिरता पर वार्तलाप करने में सहायता करने हेतु विविध विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण के अनुसार शीर्ष बैंक अपनी कार्रवाइयों से होने वाले लाभों और उनके भावी प्रभावों को मापे बिना कुछ भी नहीं करना चाहता। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये को संरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप और प्रशासनिक उपायों के मिश्रण का उपयोग करना जारी रखेगा। शीर्ष बैंक के पास उसकी देयताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त आरक्षित निधि मौजूद है।

रुपये की गिरावट के सम्बन्ध में डॉ. सुब्बाराव ने और अधिक हस्तक्षेप के संकेत दिए

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने डालर के समक्ष रुपये की गिरावट को रोकने के लिए और अधिक हस्तक्षेपों के संकेत दिए हैं। "हम स्थिति पर निरंतर रूप से निगरानी रखे हुए हैं तथा अपनी नीति से सुसंगत जो भी आवश्यक है, वह करेंगे। चालू खाते में सुधार के लिए कुछेक ढांचागत परिवर्तन आवश्यक हैं। रुपये में पिछले तीन-चार महीनों से, विशेष रूप से जनवरी-फरवरी में कुछ बढ़ोत्तरी के बाद गिरावट आ रही है। वर्तमान कमियों को सुधारने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्रवाई की है। रुपये में उतार-चढ़ाव बाहरी कारकों, पूंजीगत खाते और भुगतान संतुलन जैसे अन्य कारकों का फलन है।"

तेल विपणनकर्ता कम्पनियों (OMCs) के लिए विशेष डालर खिड़की

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि अंत: दिवसीय क्रय-विक्रय में मुद्रा के अपने जीवनकाल में सर्वाधिक न्यून स्तर पर पहुंच जाने के बावजूद रुपये के सम्बन्ध में नीति से सुसंगत

उपाय किए जाएंगे। विदेशी मुद्रा बाज़ार में डालरों के सबसे बड़े खरीदार तेल विपणनकर्ता कम्पनियों (OMCs) के लिए विशेष डालर खिड़की की संभावना को खारिज नहीं किया जाता।

ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में ब्याज दरों को कम करने की गुंजाइश कम है। हमने ब्याज दरों को घटाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हालांकि यदि आप हमारे दीर्घकालिक अथवा मध्यकालिक उद्देश्यों की तुलना में मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में हमारे पूर्वानुमानों को देखें, तो मुद्रास्फीति के दबाव मौजूद हैं। वे ब्याज घटाने की हमारे पास मौजूद गुंजाइश को सीमित कर देते हैं। माल एवं सेवा कर (GST) को लागू किए जाने से मुद्रास्फीति को घटाने में सहायता प्राप्त होगी। वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन लाने के लिए माल एवं सेवा कर के रूप में कर सुधार तथा खाद्य उत्पादकता बढ़ाने में निवेश महत्वपूर्ण हैं।"

बीमा

इर्डा ने जीवन बीमाकर्ताओं के विलयन और समामेलन का प्रारूप जारी किया

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के विलयन एवं समामेलन के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों के प्रारूप के अनुसार विलयन चाहने वाली जीवन बीमा कम्पनियों को विनियामक के पास आवेदन करने से दो माह पहले आशय पत्र प्रस्तुत करना होगा। विलयित कम्पनी के उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन के अपेक्षित न्यूनतम विनियामक स्तर से कम होने पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) विलयन को अनुमोदित नहीं कर सकता। सम्बन्धित कम्पनियों से व्यावसायिक रूप से न सम्बद्ध एक स्वतंत्र बीमांकक को प्रस्तावित विलयन एवं अंतरण के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। ये दिशानिर्देश सरकार द्वारा स्वाधिकृत भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़ कर सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ऋण प्रतिभूतिकरण से राहत मिली

प्रतिभूत सूक्ष्म वित्त ऋणों को पोर्टफोलियों को बेचने वाले सूक्ष्म ऋणदाताओं को दी गई रेटिंगों की तुलना में बेहतर श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं। इस स्थिति ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण पोर्टफोलियो खरीदने हेतु प्रेरित किया है। हैदराबाद स्थित एसकेएस माइक्रोफाइनैंस ने जनवरी-मार्च वाली तिमाही में विविध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को

लगभग 900 करोड़ रुपये की प्रतिभूत आस्तियां बेची हैं। इनमें से कुछेक पोर्टफोलियो को एसकेएस की स्वयं अपनी रेटिंग पीआर1 से कुछ अधिक पीआर1 + रेटिंग प्रदान की गई थी।

सूक्ष्म वित्त संस्था विधेयक : प्रारूप में परिवर्तनों से क्षेत्र में चेतावनी घटी बज उठी

हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत बहु-प्रतीक्षित सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 में ऋण की उच्चतम सीमा पिछले जून में विधेयक के प्रारूप में प्रस्तावित 50,000 रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी गई है। प्रस्तावित विनियामक भारतीय रिज़र्व बैंक इसे और बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर सकता है। कुछेक बैंकर यह महसूस करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप वैयक्तिक ऋणों को भी सूक्ष्म वित्त के तहत लाया जा सकता है। स्पष्ट रूप से 5 लाख रुपये पर आप मूल खण्ड को लक्ष्यांकित नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म ऋणदाता गरीबों को लगभग 36% के ब्याज पर लघु ऋण प्रदान करते हैं। प्रस्तावित अधिक ऋण की उच्चतम सीमा को स्वीकार कर लिए जाने पर यह सूक्ष्म वित्त संस्था के लिए उधारकर्ताओं की दुनिया विस्तारित कर देगी।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां बढ़ कर 295 बिलियन अमरीकी डालर हुईं

विनिमय दर की अस्थिरता को नियंत्रण में रखने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के डालर बेचने के बावजूद भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 758.3 मिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 27 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 295.361 बिलियन डालर हो गईं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डालर के समक्ष रुपये के 52.54 पर बंद होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार में चुनिंदा आधार पर हस्तक्षेप किया था। आधिकारिक आंकड़ों से यह पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में देश की प्रारक्षित निधि की स्थिति में 8.7 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जिससे वे 2.913 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं तथा विशेष आहरण अधिकार (SDR) 13.2 मिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 4.470 बिलियन अमरीकी डालर हो गए, जबकि आरक्षित स्वर्ण निधि का मूल्यांकन 27.023 बिलियन अमरीकी डालर पर अपरिवर्तित रहा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों से अपने विदेशी मुद्रा अर्जनों का आधा हिस्सा वापस लाने हेतु कहा

कमजोर पड़ते रुपये को अवलंब प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत उपायों के घुमावों की घोषणा की है। उसने कहा कि निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खातों में रखी गई शेष राशियों के 50% को रुपया शेष के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए और उसे उनके रुपया खातों में जमा कर दिया जाना चाहिए। सभी भावी अर्जनों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा अर्जक

50% (पूर्ववर्ती 100%) रकम ब्याज न अर्जित करने वाले विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खातों में बनाए रखने का पात्र होगा। दूसरे 50% को रुपया शेष राशियों में परिवर्तित किया जाना होगा।

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**18 मई 2012 के दिन**	**18 मई 2012 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 852, 4	290,000 .5
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14 055. 7	256,117. 2
ख) सोना	1, 398, 0	26, 617.9
ग) विशेष आहरण अधिकार	241, 4	4, 399.3
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	157.3	2, 866.1

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

जून 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.06920	0.628	0.710	0.866	1.038
जीबीपी	1.83775	1.2150	1.2420	1.3139	1.4185
यूरो	1.22679	0.892	0.967	1.068	1.210
जापानी येन	0.55229	0.334	0.349	0.385	0.426
कनाडाई डालर	2.03700	1.350	1.416	1.496	1.581
आस्ट्रेलियाई डालर	4.60400	2.978	3.105	3.345	3.483
स्विस फ्रैंक	0.38617	0.098	0.155	0.218	0.353
डैनिश क्रोन	1.41800	0.8850	0.9510	1.0610	1.2080
न्यूजीलैंड डालर	3.47200	2.450	2.615	2.820	3.025
स्वीडिश क्रोनर	2.80000	1.803	1.801	1.834	1.897

स्रोत भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

नयी नियुक्तियां

श्री बालकृष्ण बत्रा को आईडीबीआई बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री ज्योति घोष, महा प्रबन्धक (एसएएमजी) और ग्रुप कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग) को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में पदोन्नत किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
टीवीएस मोटर कम्पनी	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	ग्राहकों को उसके तिपहिया वाहन टीवीएस किंग खरीदने हेतु ऋण प्रदान करना
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	टाटा मोटर्स	भारत में वाणिज्यिक वाहनों का वित्तीयन करने हेतु
भारती एअरटेल	ऐक्सिस बैंक	मोबाइल पर नो फ्रिल्स खाते उपलब्ध कराने हेतु
विजया बैंक	वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर	उसके ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा अंतरण प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु
ऐक्सिस बैंक	बहरीन बैंक	बहरीन में अनिवासी भारतीयों को माई बैंक नामक इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए मुद्रा अंतरण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:

दबाव परीक्षण

हाल के वित्तीय संकट की गहनता और अवधि के फलस्वरूप कई एक बैंकों और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा यह प्रश्न किया जाने लगा है कि क्या संकट के पूर्व किए गए दबाव परीक्षण के अभ्यास पर्याप्त थे और क्या वे द्रुत गति से बदलती परिस्थितियों का सामना करने की दृष्टि से पर्याप्त थे। विशेष रूप से, उक्त संकट कई दृष्टियों से बैंकों के दबाव परीक्षण से उभरे परिणामों की तुलना में न केवल काफी अधिक गंभीर, अपितु संभवतया वह सामने आई घटनाओं की प्रतिक्रिया में दबाव परीक्षण के अभ्यासों में

विद्यमान कमजोरियों द्वारा जटिल हो गया था। उक्त संकट के अब भी समाप्त न होने के बावजूद बैंकों और पर्यवेक्षकों के लिए इस घटना से उद्भूत होने वाले सबक पहले से मौजूद हैं।

दबाव परीक्षण बैंकों द्वारा उनके आंतरिक जोखिम प्रबन्धन के अंग के रूप में तथा बासेल -II पूंजी पर्याप्तता ढांचे के माध्यम से उपयोग में लाया जाने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण जोखिम प्रबन्धन साधन है, जिसे पर्यवेक्षकों द्वरा बढावा दिया जाता है। दबाव परीक्षण बैंक प्रबन्धन को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सम्बन्धित प्रतिकूल अप्रत्याशित परिणामों के प्रति सजग कर देता है तथा इस आशय का संकेत उपलब्ध कराता है कि भारी आघात पहुंचने पर हानियों को अवशोषित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। जहां दबाव परीक्षण बिगड़ती आर्थिक स्थितियों को सहने के लिए आवश्यक पूंजी के उपयुक्त स्तर का संकेत प्रदान करता है, वहीं कोई बैंक बढ़ते हुए जोखिम के स्तरों को कम करने में सहायता के लिए वैकल्पिक रूप से अन्य कार्रवाइयां भी कर सकता है। दबाव परीक्षण एक ऐसा साधन है जो जोखिम प्रबन्धन के अन्य दृष्टिकोणों और उपायों को बढ़ाता है।

बैंकों के जोखिम प्रबन्धन में दबाव परीक्षण के महत्व को पहचानते हुए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने सुदृढ़ दबाव परीक्षण अभ्यासों और पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत जारी किए हैं। दबाव परीक्षण बैंकों द्वारा उनके आंतरिक जोखिम प्रबन्धन एवं पूंजी आयोजना के एक अंग के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। मार्गदर्शन में सुदृढ़ अभिशासन, डिज़ाइन तथा बैंकों में दबाव परीक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सिद्धांतों के एक व्यापक सेट का निर्धारण किया गया है। इन सिद्धांतों में इस प्रकार के कार्यक्रमों में उन कमजोरियों का निराकरण किया गया है, जो वित्तीय संकट में उभरी थीं। दबाव परीक्षण उस पर्यवेक्षी मूल्यांकन का एक प्रमुख घटक भी है जो कमजोरियों की पहचान करने तथा बैंक की पूंजी पर्याप्तता का निर्धारण करने में पर्यवेक्षकों की सहायता करता है। अतएव ये सिद्धांत बैंकों की दबाव परीक्षण प्रथाओं का मूल्यांकन करते समय पर्यवेक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के प्रति अपेक्षाओं का निर्धारण करते हैं।
(स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

वाटरफाल संकल्पना

एक ऐसी जीवन बीमा योजना जो धन-संपदा के पुश्तैनी अंतरण के सम्बन्ध में कर लाभ उपलब्ध कराती है। यह संकल्पना उस समय चरितार्थ होती है जब कर से छूट प्राप्त बीमा पॉलिसी किसी बच्चे या पोते-पोतियों को आवर्तित की जाती है। इस पद की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि यह बीमा योजना उस जल-प्रपात (वाटरफाल) जैसी होती है, जो केवल नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है।

शब्दावली

लंदन अंतर बैंक .द्वारा प्रस्तावित दर (लिबोर दर)

लिबोर लंदन अंतर बैंक .द्वारा प्रस्तावित दर एक ऐसी ब्याज दर है जिस पर बैंक एक-दूसरे से मुद्रा उधार ले सकते हैं। उस ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त ब्याज दर का वह न्यूनतम स्तर जिसका किसी ब्याज दर अदला-बदली (swap) में सांकेतिक मूलधन पर भुगतान किया जाता है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कुर्ला में प्रशिक्षण गतिविधियां

मई 2012 माह के कार्यक्रमों का कैलेंडर

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि	स्थल	सहभागियों की संख्या
1	ग्राहक सेवा पर संगोष्ठी	18 मई, 2012	चण्डीगढ़	120
2	"वित्तीय समावेशन" पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 से 5 मई, 2012	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला	19
3	निपुण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 से 25 मई, 2012	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला	32
4	ऋण मूल्यांकन	28 मई से 1 जून 2012	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला	39

नेतृत्व कार्यक्रम

संस्थान ने पर्सनल डिसीजन्स इंटरनेशनल (PDI), नाइंथ हाउस के सहयोग से 14 जूनन से 16 जून तक के एक त्रिदिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

सूक्ष्म वित्त सम्मेलन

संस्थान ने आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला में 14 जून, 2012 को सूक्ष्म वित्त पर सम्मेलन (conclave) कार्यक्रम की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

संस्थान समाचार

परियोजना वित्त

संस्थान आईएमएफआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त पर 18वें प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उक्त कैम्पस प्रशिक्षण 10 जून से 12 जून, 2012 तक आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50

02/05/12 03/05/12 04/05/12 08/05/12 10/05/12 15/05/12 17/05/12 18/05/12
23/05/12 24/05/12 28/05/12

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 3री को डालर के समक्ष मुद्रा 0.9% से 53.40% गिरी, जो मध्य दिसम्बर के बाद, जब वह अपने जीवन काल के सबसे न्यून स्तर 54.30 रुपये पर पहुंच गई थी, सर्वाधिक खराब स्थिति रही।
- 14 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस समय हस्तक्षेप किया, जब रुपया 53.90 के स्तर पर पहुंच गया तथा उसके 16 पैसे

बढ़ने में सहायता की। किन्तु डालर की न घटने वाली मांग ने भारतीय मुद्रा को केवल तीन व्यापार दिवसों के बाद 53.83 के पूर्ववर्ती न्यून रिकार्ड पर पहुंचने पर विवश कर दिया।

- 17वी को रुपया अमरीकी डालर के समक्ष 54.48 पर बंद हुआ, जो सभी समय के 54.58 के न्यून स्तर से दूर था।
- 21वीं को भारतीय मुद्रा अब तक्रय की स्थित को सुरक्षित करने की आपाधापी मचा दीतथा तेल विपणनकर्ता कम्पनियों ने हाजिर बाज़ार में डालर खरीदना जारी रखा।
- रुपया 21वीं को बंद भाव की तुलना में 55.40 पर बंद होने के पूर्व लुढ़क कर अब तक के सर्वाधिक न्यून स्तर 55.47प्रति डालर पर पहुंच गया। यह गिरावट साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी फिच द्वारा जापान का दर्जा घटाए जाने के बाद विशिष्टीकृत हुई, जिससे वैश्विक मनोभवों में और कमजोरी आई।
- 3 दिनों की तेजी वाली राहत के बाद अमरीकी डालर को वैश्विक मजबूती मिलने के बीच तेल कम्पनियों द्वारा मासांत की भारी डालर खरीद के कारण 29वीं को रुपया दबाव में आ गया और 55.88 के न्यून स्तर पर पहुंच गया।
- माह के दौरान रुपये में यूरो के समक्ष 0.44% की बढ़ोतरी हुई, जीबीपी और जापानी येन के समक्ष 1.10% और 5.70% घटा।

भारित औसत मांग दरें

9.00
8.80
8.60
8.40
8.20
8.00
7.80

02/05/12 03/05/12 04/05/11 07/05/12 09/05/12 10/05/12 12/05/12 14/05/12 16/05/12 17/05/12 21/05/12 24/05/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- चूंकि 7.40% के 2012 वाले सरकारी बॉण्डों के शोधन पर 33,000 करोड़ रुपये केअंतर्वाह ने नकदी रहित बैंकिंग प्रणाली को कुछ राहत पहुंचाई, 2री कि मांग दरें 8.35 / 8.40 से घट कर 8.25 / 8.30% हो गईं।
- उधार लेने वाले बैंकों से मांग के अभाव में 10वीं को मांग दरों में गिरावट हुई। एक दिवसीय मांग मुद्रा दरें 9वीं को 8.3% के मुकाबले 8.2 % के कमतर स्तर पर बंद हुईं।
- एक दिवसीय मांग मुद्रा दरें 15वीं को 8.3% से 7.8% के कमतर स्तर पर बंद हुईं। वह 8.35 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत की श्रेणी में घटती-बढ़ती रही। बैंकिंग प्रणाली में प्रचुर चलनिधि के होने के कारण उधार लेने वाले बैंकों से मांग का अभाव दिखाई देता है।
- उधार लेने वाले बैंकों से नयी खरीद का सहारा पा कर मांग मुद्रा दरें 28वीं को 8.1% के बंद वाले स्तर से 8.15% के उच्चतर स्तर पर बंद हुईं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

17500
17100
16700
16300
15900
15500

02/05/12 04/05/12 10/05/12 14/05/12 16/05/12 17/05/12 21/05/12 22/05/12
23/05/12 25/05/12 28/05/12

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जून, 2012